



आगे का रास्ता

आम चुनाव में भाजपा और एनडीए को मिली असाधारण जीत यह बताती है कि नरेंद्र मोदी पर न केवल देश के लोगों का भरोसा कायम है, बल्कि वे उनकी ओर पहले से अधिक उम्मीद से देख रहे हैं।

नरेंद्र मोदी की अगुआई में भाजपा और एनडीए को आम चुनाव में लगातार दूसरी बार मिली असाधारण जीत भारतीय संसदीय राजनीति के दुर्लभ क्षणों में से एक है, जिसने दिखा दिया कि देश की जनता का न केवल उन पर भरोसा कायम है, बल्कि वह उनकी ओर पहले से कहीं अधिक उम्मीद से देख रही है। वह सबका साथ सबका विकास के वादे के साथ सत्ता में आए थे, जिसकी थाह पाने में कांग्रेस, सपा और बसपा सहित तमाम विपक्षी दल विफल रहे हैं, क्योंकि वे अपने राजनीतिक खांचों से बाहर निकल ही नहीं पाए। भाजपा तीन सौ के आंकड़े के करीब है, तो इसके पीछे नरेंद्र मोदी का करिश्मा है, जो साहसिक फैसले लेने से नहीं हिचकते। फिर वह आर्थिक मोर्चे पर नोटबंदी या जीएसटी लागू करने

का मामला रहा हो या सामाजिक मोर्चे पर किसानों को सालाना छह हजार रुपये की मदद या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में सरहद कर जाकर आतंकी शिविरों पर हवाई हमले की मंजूरी। दरअसल इतनी बड़ी जीत के बाद उनके सामने चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं। उज्ज्वला, जनधन जैसी योजनाओं ने एक बड़ी आबादी में विश्वास पैदा किया, लेकिन रोजगार के मोर्चे पर अब भी काफी हताशा है। महंगाई को नियंत्रित करने में सरकार सफल रही है, मगर खपत और खर्च बढ़ाए बिना अर्थव्यवस्था को गति नहीं मिल सकती। भारत मध्य आय वाला देश (प्रति व्यक्ति 2,000 डॉलर सालाना आय) बनने के करीब है, जिसमें नया आकांक्षी वर्ग उभर रहा है, तो दूसरी ओर हाल के वर्षों में कृषि क्षेत्र में भारी हताशा देखी गई है। इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की जरूरत होगी। मोदी सरकार ने पिछली

बार स्मार्ट सिटी पर काम तो शुरू किया, मगर उसके सार्थक नतीजे सामने नहीं आए हैं, जबकि दुनिया की तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बनते भारत में शहरीकरण में तेजी लाने की जरूरत है। चीन में शहरीकरण की दर 59 फीसदी है, जबकि भारत में 34 फीसदी! देश में कारोबारी सुगमता बढ़ी है, मगर इसके साथ ही नई सरकार को बैंकिंग सुधारों को प्राथमिकता में रखना होगा। नतीजे आने के साथ ही मुंबई शेयर बाजार के सूचकांक ने पहली बार चालीस हजार का आंकड़ा पार कर बाजार के उत्साह को रेखांकित किया है, इसे बरकरार रखने के लिए निवेशकों का विश्वास जीतना जरूरी है। जीत के बाद मोदी ने समावेशी और समृद्ध भारत के निर्माण की बात कही है, उम्मीद करनी चाहिए कि उनकी सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी, आगे का रास्ता उनके अनुकूल है।

बंगाली क्षेत्रीयता से जा मिला केसरिया

इस लोकसभा चुनाव का मूल पाठ अगर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सत्ता में वापसी से जुड़ा था, तो पश्चिम बंगाल का चुनावी नतीजा उसी का उप-पाठ है। जैसे केंद्र की सत्ता में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की धमकेदार वापसी हुई है, वैसे ही पश्चिम बंगाल में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया है और वह सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की सीटों के नजदीक पहुंच गई है। साफ है कि वाम दलों का वोट बैंक भाजपा में जा मिला है। यह लेफ्ट के लिए बड़ा झटका है। नरेंद्र मोदी ने तृणमूल प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 'स्पीड ब्रेकर दीदी' बताया था। वह सच कह रहे थे। ममता बनर्जी ने बंगाल में भाजपा को निर्णायक जीत हासिल करने से रोक दिया है, पर केसरिया पार्टी तृणमूल के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। बंगाल में यह केसरिया लहर तीन कारणों से महत्वपूर्ण है-



सुबीर भौमिक
वरिष्ठ पत्रकार

वैसे तो बंगाल 1947 में धार्मिक आधार पर विभाजित हुआ था, पर यहाँ हिंदुत्ववादी पार्टी कभी मजबूत नहीं हुई। कांग्रेस, वाम मोर्चा और तृणमूल- इन तीनों का ही धर्मनिरपेक्ष स्वरूप रहा है। पर इस चुनाव में तृणमूल को भारी चुनौती देकर भाजपा ने बंगाल में आजादी से बाद की राजनीतिक परंपरा को ही पूरी तरह बदल दिया है। अगर भाजपा बंगाल में अपने इस जनाधार को बरकरार रखती है, तो इससे साबित हो जाएगा कि हिंदुत्व की राजनीति यहाँ के लिए बाहरी या त्याज्य विचारधारा नहीं है, बल्कि यह बंगाल की मुख्यधारा का अंग बन जाएगा।

वर्ष 1977 से पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीय पार्टी को कभी ऐसी चुनौती नहीं मिली, जैसी इस बार भाजपा ने तृणमूल को दी है। पिछले चालीस साल से बंगाल ने अपना विशिष्ट राजनीतिक तरीका अखिरापर कर रखा था। इसके तहत पहले वाम दलों ने कांग्रेस और भाजपा को चुनौती दी, फिर तृणमूल ने भाजपा के खिलाफ असामान्य आक्रामकता का परिचय दिया। वरिष्ठ पत्रकार चंदन मित्र कहते हैं कि अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा तृणमूल को मात देकर सत्ता में आ सकती है। इसका मतलब यह है कि बंगाल अपनी विशिष्ट पहचान को राष्ट्रीय विमर्श में बदल देगा। यदि अब कोई हिंसा भड़कती है, तो राष्ट्रपति शासन का विकल्प खुला रहेगा। नरेंद्र मोदी तक कह चुके हैं कि कानून-व्यवस्था के मामले में बंगाल का हाल जम्मू-कश्मीर से भी बुरा है। रूपा गांगुली कह ही चुकी हैं कि तृणमूल को हिंसा पर अगर अंकुश लगाया जाता, तो भाजपा 30 सीटें जीत सकती थी। जिस तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ, बांग्लादेशी घुसपैठियों से लेकर एनआरसी का मामला उठा और तुष्टीकरण पर खाई बढ़ी, उससे न केवल हिंदू-मुस्लिम के बीच, बल्कि धर्मनिरपेक्ष रझान वाले हिंदू और हिंदुत्ववादी कोच राजवंशी, गोरखालैंड की मांग करते नेपाली, संथाल और मुंडा आदिवासी समूह तथा हिंदी भाषियों के बीच भी खाई बढ़ेगी। ऐसे ही भाजपा की आक्रामकता तथा एनआरसी का डर बांग्लादेश को चीन के नजदीक ले जाएगा।



जो हुआ, सो यों हुआ!

ह

मारे एक वरिष्ठ आलोचक मित्र ने पिछले हफ्ते कहा था, हताशा आदमी गाली देता है और कमजोर आदमी शाप। अधूरी विजय वाले दुश्मन को कमजोरी पर नजर रखते हैं, पक्की जीत के विजेता दुश्मन की ताकत पर। मोदी विरोध की धुरी इन्हीं बिंदुओं पर घूम रही थी। उधर शाप और गालियाँ चलती रहीं, इधर नरेंद्र मोदी ने अपनी राजनीतिक समझ के चलते विरोधियों को अपने ही मैदान में ला खड़ा किया। वे यह रूपक स्थापित करने में सफल रहे कि विरोधियों की सामूहिकता सिर्फ और सिर्फ मोदी के प्रति घृणा और व्यक्तिगत स्वार्थों की जमीन पर टिकी हुई है। जो उनके मुहावरों की नकल करके मुहावरे गढ़ने का जोहर दिखाने में लगे थे उनके पास था भी क्या? यही कि मीडिया बिका हुआ है, कि हर चीज खरीद ली गई है, कि यह आदमी रहा तो लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। और कि, हर आदमी की वापसी एक 'नीच ट्रेजिडी' होगी। यह कामनाओं का स्वर्ग था।

राजनीति हो या जीवन हर एक को सैद्धांतिक रूप से अपनी निष्ठाओं के साथ उपस्थित होना ही चाहिए। लेकिन कामनाएं और यथार्थ दो अलग चीजें हैं। जब आप चाहते हैं कि नारियल को पीपल कहा जाए और जो नारियल को पीपल न कहे, वह बिका हुआ मान लिया जाए तो यह आकलन खूद के लिए ही खतरनाक हो जाता है। यह भी सिद्ध तथ्य है कि संदेह पैदा करना भी युद्ध की एक तकनीक होती है। यह एक कलात्मक चालाकी है कि अपनी कमजोरी ढंकना हो तो दूसरे की क्षमता पर संदेह खड़ा कर दिया जाए। यह चीज अदालत से लेकर रेफरी तक, ईवीएम से लेकर एक्जिट पोल तक- सभी जगह सुविधापूर्वक लागू होती है। लेकिन इससे आगे के रास्ते नहीं खुलते। एक बौद्धिक लड़ती हो सकती है, मसखरी नकल हो सकती है लेकिन वस्तु सत्य ओझल हो जाता है। इसीलिए विस्मय की बात यह नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी ब्रांड अपील कैसे बनाई, बल्कि यह है कि अंत तक बहुत से विद्वज्जन क्यों पीपल के पेड़ को नारियल कहलवाने की जिद में ही होम हो गए।

2014 में इन पंक्तियों के लेखक ने लिखा था कि विरोधियों के पास मोदी की इस विजय का एक ही 'तोड़' है। अब दलितों और मुसलमानों का तेज मसाला तैयार किया जाएगा और एकल हिन्दुत्व को ब्राह्मणवादी वर्चस्व के अतीत की भयावह तस्वीर से मिलाकर पेश किया जाएगा। 2019 तक आते-आते विपक्ष तो उसी पर लगा रहा, लेकिन मोदी ने इसे चुनौती की तरह लिया। और अपनी सोची-समझी सक्रियता से चौरफा मार का नक्शा बनाया। साहस और अविचलता को ब्रांड का केंद्रीय गुण बनाया और विरोधियों के हर हमले को लाभ के सामान में तब्दील कर लिया गया।

पहले ही दिन से मोदी और मोदी-विरोधी-दोनों अपने-अपने काम पर रहे हैं। पार्टी में भी और पार्टी के बाहर भी। गोवा की बैठक में मोदी का नाम प्रस्तावित करने का विरोध करके अयोध्या-स्थी आडवाणी तक अरुभूत धर्मनिरपेक्ष हो गए थे। मोदी ने दिल्ली में कदम रखा तो संसद में प्रणाम से शुरू करके, विदेश यात्राओं तक, नवराज के ओबाभा-नींबू-पानी से लेकर सऊदी अरब में मंदिर की जमीन तक, सर्जिकल स्ट्राइक से बालाकोट तक एक मोर्चे पर काम किया। साथ-साथ उज्ज्वला,

स्वच्छता, पटेल, बोस, डिजिटल, आयुष्मान और आवास योजना की सब्सिडी के साथ जन-धन खातों समेत दूसरे मोर्चे पर काम किया। फिर नोटबंदी, जीएसटी से जुड़ते हुए राजनीतिक विरोधियों को अपनी गंगा आरती, विश्वनाथ पूजा और केदारनाथ से इस तरह निरस्त करने की कोशिश की कि उन्हें अपनी 'हिंदू पहचान' के सार्वजनिक मान से कोई संकोच क्यों होना चाहिए? इसका दूसरा अर्थ यह था कि जातियाँ तोड़ी जाएँ, नए तंत्र का आत्मविश्वास खड़ा किया जाए, सांप्रदायिकता के भय का नैरेटिव बदला जाए और पारंपरिक समीकरणों को ध्वस्त करने में अपनी राजनीतिक शक्ति कैसे लगाई जाए? 'सवर्ण पिछड़ों' और 'मध्यमार्गी सवर्णों' का मिश्रण कैसे विश्लेषित किया जाए। क्षेत्रीय शक्ति की धुरी बनी खास जातियों की राजनीति को शेष अशक्त जातियों की राजनीति से कैसे निरस्त किया जाए? दूसरी तरफ वैचारिक मोर्चा यह था

संदेश दिया गया कि सत्ता के वे संचालक जो पीछे रहकर दिल्ली से न्यूयॉर्क तक विमर्श खड़ा करते हैं, आमजन के ब्रांड को सहन नहीं करते, फिर भी वो खड़ा है तो इसीलिए कि आखिरी आदमी उसके साथ है।

यह भी स्थापित होता चला गया कि यह शंख ध्वनि से रोगाणु मारने वाला ठस परिहास-पात्र नहीं है, समकालीन शब्दावली से लैस ब्रांड है।

कि भीतर की ग्रियों, अतीत के भ्रष्ट शासन तथा अस्ताचलगामी विचारधाराओं का नैरेटिव कैसे तैयार किया जाए? फिर यह भी स्थापित होना चाहिए कि यह शंख ध्वनि से रोगाणु मारने वाला ठस परिहास-पात्र नहीं है, समकालीन शब्दावली से लैस ब्रांड है।

जवाब में एक पिछड़े, मामूली घर के, चौरफा घेर लिए गए साहसी, सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े ब्रांड की एक कोर शक्ति यह स्थापित हुई कि वह बौद्धिक पलीट को चुनौती देता है। 'खान मार्केट' और 'लोधी गार्डन' इसीलिए गुंजे क्योंकि इससे सीधी स्थापना होती थी कि सत्ता के वे कथित संचालक जो पीछे रहकर दिल्ली से न्यूयॉर्क तक विमर्श खड़ा करते हैं, आमजन के ब्रांड को सहन नहीं करते, फिर भी वो खड़ा है तो इसीलिए कि आखिरी आदमी उसके साथ खड़ा है। वह आम जनता से शक्ति लेकर 'पलीट' को चुनौती देने का साहस रखता है। यह नए समय की ध्वनि को सुनना था। स्वातंत्र्योत्तर भारत में मध्य-वाम से मध्य-दक्षिण का सीधा साहसिक एलान करना था। साथ ही तकनीक, आधुनिकता और सांस्कृतिक वैभव का बिम्ब भी कौशलपूर्वक स्थापित किया जाना था। इसके अपने जोखिम थे जिन्हें कभी किसी ने नहीं उठाया था। नरेंद्र मोदी ने इसे उठाया और समांतर विमर्श की धारा खड़ी कर दी।

विपक्षी इसमें से सिर्फ कोई एक खास जाति और सिर्फ

के साथ शक्ति संचित की और प्रतिपक्ष को छिन्न-भिन्न कर दिया।

नोटबंदी-जीएसटी अमीरों की चोरी के विरुद्ध गरीबों का नैरेटिव बन गए, मसूद अजहर स्वाभिमान और साहस का! आरती सांस्कृतिक वैभव का योग बन गई और मोबाइल की फ्लैश टॉर्च नई उम्र की नई फसल!

अब जब इस संश्लिष्ट जीत का सत्य दिखाई देने लगा है, तब भी इस ब्रांड से कुछ 'मासूम' वही आदिम सवाल कर रहे हैं, 'तो क्या अब हिंदू राष्ट्र, बनेगा?'

समझ जाहए। यदि अब भी ब्रांड मोदी के विरोधी उसकी शक्तियाँ समझ कर कारगर रणनीति बनाने के बजाय ऐसे जुबानी धिक्कार से ही काम चलाएंगे तो यह ब्रांड उससे आगे के नैरेटिव बनाएगा और फिर-फिर अपनी कोर-वैल्यू रिसाइकल करेगा।

तब तक, जब तक कि संबोधित और संबोधन के पारस्परिक संबंध ही नहीं बदल जाते!

जमीन पर विफल महागठबंधन

लोकसभा चुनाव : पर्दे के पीछे का खेल खत्म

यह चुनाव भारत के चुनावी इतिहास का मानक स्तंभ बन गया। जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी व राजीव गांधी के बाद नरेंद्र मोदी चौथे ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने बड़ी संख्या में सीट जीतने में कामयाबी पाई है। 2014 में भी उन्हें ऐतिहासिक जनमत मिला था, उस समय वह अच्छे दिन के वादे और 'सबका साथ सबका विकास' का नारा देकर सत्ता में आए थे। इस चुनाव में भी कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों के साथ जाटल व पेचीदा लड़ाई लड़कर उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है।

भाजपा के विरोध में विपक्ष ने अलग-अलग राज्यों में गठबंधन किए। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जहां एकला चलो की नीति पर रही, वहीं कई राज्यों में वह विभिन्न दलों के साथ गठबंधन में रही। विरोधी खेमे के गठबंधन का सबसे बड़ा उदाहरण अखिलेश व मायावती का जुड़ना था।

यह कयास लगाया गया कि महागठबंधन यादव-दलित वोटों को एक साथ ले आएगा। ऐसा लगा था कि महागठबंधन को हराना मुश्किल होगा। लेकिन नतीजे चौंकाने वाले रहे। महागठबंधन विफल साबित हुआ।

कांग्रेस शुरू में महागठबंधन का हिस्सा बनने वाली थी। बाद में उसने अकेले चुनाव लड़ा। कांग्रेस यहां सोनिया गांधी की रायबन्दी सीट के अलावा कोई सीट नहीं जीत पाई। बिहार में गठबंधन बुरी तरह पराजित हुआ। नीतीश व मोदी के दमदार नेतृत्व का सामना करने के लिए कम उम्र के तेजस्वी को अकेले छोड़ दिया गया। राजद के प्रमुख नेता अपनी सीट नहीं बचा पाए। झारखंड में भी कई पार्टियों ने गठबंधन किया, पर विफल रहे।



मनीषा प्रियम

उत्तर प्रदेश में यादव और दलित वोटों को एक साथ लाना चाहता था महागठबंधन, पर ऐसा नहीं हुआ।

जबकि भाजपा द्वारा किए गए छोटे-छोटे गठबंधन कामयाब हुए। इससे साफ है कि जनता ऐसी परोक्ष राजनीति को खारिज करती है। अब पर्दे के पीछे बैठकर कोई यह तय नहीं कर सकता कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तीन राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा को कड़ी टक्कर देने वाली कांग्रेस इस चुनाव में पूरी तरह विफल रही। सबसे अप्रत्याशित नतीजे पूर्वोत्तर से आए। इन राज्यों को मुख्यधारा से पृथक समझा जाता था। किंतु मोदी-शाह की राजनीति में यहां की राजनीति को भाजपा ने अपनी ओर लाने के सफल प्रयास किए। इस चुनाव में मोदी सरकार की कई योजनाओं का अरार दिखा। लगभग हर राज्य में मोदी की लहर रही।

दक्षिण : नहीं भांप पाया उत्तर का मिजाज

दक्षिण में भी मचाई हलचल

दक्षिण भारत के दो बड़े नेता चंद्रबाबू नायडू और एमके स्टालिन उत्तर भारत के मतदाताओं का मानस नहीं पढ़ पाए। नरेंद्र मोदी ने चंद्रबाबू नायडू को मात

दी है। अब उन वायदों का क्या होगा, जो नायडू ने किए थे। पिछले कुछ समय से वह दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता में व्यस्त थे। टीडीपी आंध्र प्रदेश में धराशाही हो गई। अब क्या नायडू इसका दोष ईवीएम पर मढ़ेंगे?

दूसरी ओर, जगन मोहन रेड्डी धीरे-धीरे मतदाताओं का समर्थन पा रहे थे। पिता की मृत्यु के बाद सोनिया और राहुल गांधी ने जिस तरह उनसे दूरी बनाई उससे उनके प्रति लोगों में सहानुभूति जगी। विधानसभा चुनाव जीतकर जगन जहां आंध्र के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, वहीं लोकसभा चुनाव में भी टीडीपी को पछाड़कर उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। आंध्र के सभी इलाकों और सभी वर्गों के बीच वाईएसआर का रॉश है कि प्रदर्शन इतना बेहतरीन रहा है कि टीडीपी के लिए कुछ करते नहीं बना।

तेलंगाना में हाल में हुए विधानसभा चुनाव में टीआरएस को भारी जीत मिली थी। पर लोकसभा चुनाव में बदतर प्रदर्शन के साथ फेडरल फ्रंट के जरिये केंद्र में बड़ी भूमिका निभाने की इच्छा रखने की चंद्रशेखर राव की

उम्मीदें भी ध्वस्त हो गईं। ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म के खिलाफ केसीआर की कुछ टिप्पणियाँ मतदाताओं को अच्छी नहीं लगीं। हालांकि भाजपा के साथ कांग्रेस ने भी वहां अच्छा प्रदर्शन किया है। हिंदुत्व का असर कर्नाटक में भी देखने को मिला है, जहां भाजपा का प्रखर शानदार रहा है। उसने कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन को बुरी तरह बेअसर कर दिया है।

तमिलनाडु में द्रमुक विजेता बनी है, जो मोदी-विरोधी रुख के बारे में बताता है। पर द्रमुक को चाहे जितनी भी सीटें मिलें, राष्ट्रीय राजनीति में वह अप्रसंगिक ही रहेगी। ऐसे ही केरल में कड़ी मेहनत के बावजूद भाजपा को सफलता नहीं मिली।

साफ है कि दक्षिण भारत उत्तर भारत का मूड भांपने में चूक गया, जहां भाजपा की आंधी चली है। दक्षिण भारत में राष्ट्रवाद कोई मुद्दा नहीं था। अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर्नाटक और तमिलनाडु में अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। भाजपा तमिलनाडु में त्रिपुरा जैसी उपलब्धि दर्ज करना चाहती है, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। अगले एक-दो साल में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ऐसी रूपरेखा जरूर बनाएगी, जिससे कि अगले लोकसभा चुनाव में दक्षिण भारत की कुल 130 सीटों में से उसे 50 सीटें जरूर मिलें।



आर राजगोपालन
वरिष्ठ पत्रकार

अगले चुनाव से दक्षिण से 50 सीटें जीतने का रहेगा लक्ष्य।

देश को बदल देने वाला है यह जनादेश

नरेंद्र मोदी : निर्णायक नेतृत्व के पर्याय

हमारे देश में कई ऐसे चुनाव हुए हैं, जो ऐतिहासिक रहे हैं, इस बार का चुनाव भी ऐसा ही है। इस बार का जनादेश हिंदुस्तान को बदलने वाला है। हिंदुस्तान की जो राजनीति है, हिंदुस्तान का जो समाज है और हिंदुस्तान का लोकतंत्र किस तरह से काम करेगा, इन सबको प्रभावित करने वाला है। एक बात तो स्पष्ट है कि हमारे समाज और हमारी राजनीति का भी हिंदूकरण हो चुका है। जो भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में आना चाहेगी, उसे इस चीज को मद्देनजर रखना पड़ेगा।

इस बार हिंदू-मुस्लिम संघर्ष को लेकर उस मापने में ध्रुवीकरण नहीं हुआ, पर राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा को मुद्दा बनाकर ध्रुवीकरण किया गया। राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा ने हिंदू पहचान को और मजबूत किया। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हिमायती के रूप में अपनी छवि गढ़ी। गरीब तबका कभी कांग्रेस का मजबूत वोट बैंक था। पर आज गरीब भाजपा का वोट बैंक बन गया है, क्योंकि आज गरीब कहता है कि नरेंद्र मोदी ही गरीबों के लिए कुछ कर सकते हैं। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद जाति की जो राजनीति शुरू हुई थी, उसमें भी भाजपा ने संघ लगाई है। मैं यह तो नहीं कहूँगी कि उसे पूरी तरह खत्म कर दिया गया है, पर उसमें संघ जरूर लगाई गई है। अगर ऐसा नहीं हुआ होता, तो उत्तर प्रदेश में महागठबंधन का प्रदर्शन बेहतर होना चाहिए था। गणित बताता है कि यदि मुसलमान, जाटव और यादव इकट्ठा हो जाएँ, तो वे बड़ी ताकत बन सकते हैं। पर इनका वोट बिखर गया, क्योंकि नीजवान यादव और नीजवान जाटव ने मोदी को वोट दिया है। हमारे देश में युवाओं एवं महिलाओं का एक



नीरजा चौधरी

युवाओं, महिलाओं और पहली बार के मतदाताओं ने जाति से ऊपर उठकर मोदी के पक्ष में वोट दिया।

नया आकांक्षी वर्ग उभरा है, जिसने मोदी को वोट दिया है। इसके साथ अति पिछड़ी जातियाँ, चाहे उत्तर प्रदेश में हों या बिहार में, आज मोदी के पीछे मजबूती से खड़ी हैं। अब ऐसा लगता है कि आगे देश की जो नीतियाँ बनेगी, चाहे विदेश नीति हो या घरेलू नीति, वे ज्यादा आक्रामक होंगी। पर नई सरकार के सामने आर्थिक और बेरोजगारी की चुनौती भी होगी। यह चुनाव नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता के बारे में था। एक नई बात देखने को मिली कि लोगों ने पार्टी नहीं, नेता को ध्यान में रखकर वोट दिया। बालाकोट हवाई हमले के बाद यह धारणा और मजबूत हुई कि मोदी ही दूसरे के घर में जाकर टक्कर दे सकते हैं, उन्हीं में निर्णायक फैसले लेने और कुछ बड़ा करने की क्षमता है।